विकास बहल, *न्यायमूर्ति के समक्ष*

रुकसाद-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी 2022 का सी. आर. ए.-एस. No.253

17 फरवरी, 2022

किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, **2000**-खंड **12**-एक किशोर को जमानत, जो कानून के साथ संघर्ष में है, नियम है जब तक कि किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, **2000** की खंड **12** में उल्लिखित अपवादों में से किसी एक के तहत शामिल नहीं है-जमानत दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिनियम की खंड 12 के तहत एक आवेदन में, जमानत नियम है और केवल उस स्थिति में जब अपीलकर्ता अधिनियम की खंड 12 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के तहत आता है कि जमानत आवेदन को खारिज किया जा सकता है।आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम की खंड 12 के उक्त प्रावधानों पर विचार भी नहीं किया गया था और इसमें यह दूर से भी नहीं देखा गया था कि अपीलकर्ता का मामला किसी भी अपवाद के दायरे में आता है।कथित घटना के दिन अपीलकर्ता की आयु 16 वर्ष और 2 महीने थी। अभियोजन पक्ष के संस्करण के अवलोकन से पता चलता है कि 11 आरोपी हैं और हालांकि, कुछ अभियुक्तों को विशिष्ट चोट लगी थी, लेकिन वर्तमान अपीलकर्ता को कोई विशिष्ट चोट या विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता **24-07-2019 से** हिरासत में है और 30 गवाह हैं, जिनमें से 15 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है और इस प्रकार, वर्तमान महामारी को देखते हुए मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है।यहां तक कि सह-अभियुक्त आमिर, जो कथित घटना की तारीख को एक वयस्क था, को पहले ही इस अदालत की एक समन्वय पीठ द्वारा सीआरएम-एम 35750-2020 में पारित 16.11.2021 के आदेश के अनुसार **नियमित जमानत दे दी गई है** और उसकी हिरासत की अवधि वर्तमान अपीलकर्ता की हिरासत से कम थी।

(पैरा 14) ने आगे कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह द्वारा पारित दिनांक 29-04-2020 को पारित विवादित आदेश को दरकिनार / खारिज कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/मुचलके के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

(विकास बहल, जे.)

439

अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/इलाखा मजिस्ट्रेट और किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं होने के अधीन।

(पैरा 15)

सौरभ भाटिया, अधिवक्ता,

अपीलकर्ता के लिए।

मनीष डडवाल, एएजी हरियाणा।कमल दीप सेहरा, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता

विकास बहल**, जे. (ORAL)**

(1) वर्तमान अपील में चुनौती अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह द्वारा पारित दिनांक 29.04.2020 के आदेश को दी गई है, जिसके अनुसार वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की खंड 12 के तहत दायर जमानत के लिए आवेदन, 2019 की प्राथमिकी No.148 में, खंड 148,149,323,342,506,307 और भा.दं.सं. सी. के तहत, जो पुलिस स्टेशन रोजा मेव, जिला नूंह में दर्ज है, खारिज कर दिया गया है।

(2) अभियोजन पक्ष के मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्तमान प्राथमिकी शिकायतकर्ता उदका गांव के निवासी श्रीचंद के बेटे कुंदन के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसने कहा था कि उनके गांव में ममरेज के बेटे जमशेद और रुस्तम के बेटे अख्तर के बीच 15-07-2019 को झगड़ा हुआ था; उस का भतीजा नवीन पुत्र महावीर सोहना जा रहा था और जमशेद ने उससे लिफ्ट मांगी और फिर वह नवीन के साथ सोहना गया और उक्त जमशेद ने उक्त झगड़े के संबंध में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। 19-07-2019 को, जमशेद और अख्तर के बीच विवाद को हल करने के लिए एक

पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें एक समझौता हो गया था और जब नवीन अपने घर वापस जा रहा था, शिकायतकर्ता उसके साथ था और रास्ते में मकसूदन-पत्नी और सरजीना-अख्तर की बेटी ने घर की छत से ईंटें उठाईं और उसे नवीन पर फेंक दिया और उसके सिर पर मार डाला।सिर में चोट लगने के बाद नवीन को गंभीर चोट लगी और इस बीच, नाशरुद्दीन के बेटे जेकम ने नवीन को घर के अंदर खींच लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया।इसके बाद अख्तर, उसकी पत्नी, बेटी और बेटे साजिद ने घर में नवीन को पीटा और जब शिकायतकर्ता उसे बचाने गया तो साजिद, अख्तर, जेकम, सरजिना और मकसूदन ने उसे पत्थरों और क्रिकेट के बल्ले से मारा और इस बीच राम अवतार भाई और सतीश बेटे के साथ नितेश और प्रेम वहां आए और उसके बाद रुकसर (वर्तमान याचिकाकर्ता), सैकुल, सरजिना, मकसूदन, साजिद, अख्तर ने उन पर लाठी, डंडे, क्रिकेट के बल्ले और पत्थरों से हमला किया।

और परिणामस्वरूप, नवीन ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया और भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के तहत अपराध जोड़ा गया।इसके बाद, वर्तमान अपीलकर्ता ने अधिनियम की खंड 12 के तहत जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह ने खारिज कर दिया था।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, अपीलकर्ता को **किसी भी** विशिष्ट चोट **के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और न ही** उसे किसी विशिष्ट हथियार से लैस कहा गया है और हालाँकि, छड़ी (डंडा) की बरामदगी अपीलकर्ता से की गई है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद जमशेद और अख्तर के बीच था और मृतक के सिर पर **चोटें** सह-अभियुक्त द्वारा **दी गई थी,** जिसे अभियोजन पक्ष के संस्करण में विशेष रूप से विस्तृत किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 11 आरोपी हैं और वर्तमान अपीलकर्ता को केवल अख्तर का बेटा होने के बहाने नामित किया गया है।यह तर्क दिया जाता है कि कथित घटना की तारीख पर, अपीलकर्ता की आयु 16 वर्ष और 2 महीने थी।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आमिर (सह-अभियुक्त), जो घटना की तारीख को वयस्क था, को पहले ही इस अदालत की एक समन्वय पीठ द्वारा सीआरएम-एम-35750–2020 में पारित

दिनांक 16-11-2021 के आदेश के अनुसार नियमित जमानत दे दी गई है और उक्त आमिर 29-07-2019 के बाद से हिरासत में था, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता घटना के समय 18 वर्ष से कम उम्र होने के अलावा 24-07-2019 के बाद से हिरासत में है और इस प्रकार, वर्तमान अपीलकर्ता की हिरासत उक्त आमिर की हिरासत से अधिक है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल 30 गवाह हैं, जिनमें से 10 से पूछताछ की गई है और हालांकि, 5 की छोड़ दी गई है, 15 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अपीलकर्ता वयस्क था, तो भी हिरासत अवधि के आधार पर और इस आधार पर कि उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, वह नियमित जमानत पर रिहा होने का हकदार है।यह भी कहा गया है कि विवादित आदेश पारित करने के समय, न्यायालय ने अधिनियम की खंड 12 और सामान्य सिद्धांत पर भी विचार नहीं किया था कि जमानत एक नियम है न कि जेल, और यह भी विवादित आदेश में नहीं देखा गया है कि अपीलकर्ता का मामला अधिनियम की खंड 12 में उल्लिखित तीन अपवादों के तहत आता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी बताया है कि इससे पहले अपीलकर्ता ने एक सी. आर. आर.-906-2021 दायर किया था, जिसमें शिकायतकर्ता के वकील द्वारा प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी और 18.11.2021 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः-

"यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह द्वारा पारित दिनांक 29-04-2020 के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'अधिनियम') रुकसद बनाम हरियाणा राज्य की **धारा 12 के तहत याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया गया।**

(विकास बहल, जे.)

441

।

शुरुआत में, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वास्तव में वर्तमान मामले में, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है और केवल अधिनियम की खंड 101 (5) के तहत अपील दायर की जा सकती है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 101 के उपधारा(5) के अनुसार, बाल न्यायालय के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार है और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 के लिए आगे का संदर्भ दिया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"(20) "बाल न्यायालय का अर्थ है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के तहत स्थापित न्यायालय या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के तहत एक विशेष न्यायालय, जहां भी मौजूद है और जहां ऐसी अदालतें नामित नहीं की गई हैं, सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने की अधिकार क्षेत्र है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित आदेश उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा101 (5) के तहत केवल एक अपील होगी और एक बार अपील का विशिष्ट प्रावधान होने के बाद आपराधिक संशोधन का शेष प्रावधान लागू नहीं होगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति को देखते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 101 (5) के तहत अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उक्त बयान के मद्देनजर वर्तमान याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।"

(4) उसी के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने अब कानून के अनुसार वर्तमान अपील दायर की है।

(5) राज्य के विद्वान वकील के साथ-साथ शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने वर्तमान अपील का विरोध किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता के कार्य के कारण, अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, नवीन की मृत्यु हुई है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है

कि विवादित आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(6) इस न्यायालय ने पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और पेपरबुक का अध्ययन किया है।

(7) 2015 के अधिनियम की खंड 12 पर ध्यान **देना** प्रासंगिक है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

'जब कोई व्यक्ति, जो **स्पष्ट रूप से** एक बच्चा है और जिस पर जमानतीय या गैर-जमानतीय अपराध करने का आरोप है, पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या हिरासत में लिया जाता है या बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मुचलके के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगाः-

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह से रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई की संभावना है

- उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जोड़ना या
- उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना या
- व्यक्ति की रिहाई **न्याय** के उद्देश्यों को विफल कर देगी, और बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों और उन परिस्थितियों को दर्ज करेगा जिनके कारण ऐसा निर्णय लिया गया।"

(8) अधिनियम की उपरोक्त खंड 12 के अवलोकन से पता चलेगा कि नाबालिग के मामले में जमानत नियम है न कि जेल और इसे केवल उस स्थिति में अस्वीकार किया जाना चाहिए जब अदालत इस सामग्री के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामला अधिनियम की खंड 12 में उल्लिखित तीन अपवादों के तहत आता है।

(9)इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ सी. आर. आर.-1019-2020 में

"गुरकिरत @गोरा बनाम हरियाणा राज्य में पारित किया गया है

इसके अंतर्गतः-

“इस पुनरीक्षण याचिका में **माननीय** मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 31.05.2020 के आदेश के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.07.2020 के आदेश को स्थापित करने के लिए है, **जिसके तहत** याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में प्राथमिकी सी.') की और 506 **धारा 302**,323,341 **के साथ पठित धारा 34 और 506** के तहत दर्ज किया गया था, जिसे **एफ.आई.आर. 99 दिनांक 14-03-2020 में** पुलिस स्टेशन तरौरी, जिला करनाल में खारिज कर दिया गया था।

रुकसाद बनाम हरियाणा राज्य

(विकास बहल, जे.)

443

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्राथमिकी आर. लखविंदर सिंह द्वारा दी गई शिकायत पर दर्ज की गई थी कि वह मजदूरी का काम **करता है** और उसके दो बच्चे हैं।

शिकायतकर्ता के साथ उसका बेटा अस्पी @हैप्पी भी मजदूरी का काम कर रहा था। लगभग 1 साल पहले, याचिकाकर्ता के पिता कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे पर आरोप लगाया है कि उसने **उसकी** भतीजी को छेड़ा था और उसके बाद, एक पंचायत बुलाई गई थी और मामले **में** समझौता किया गया था, लेकिन आरोपी को उसके बेटे अस्पी @हैप्पी के खिलाफ **दुश्मनी रखे थे**। 13.03.2020 **को सांय** पर लगभग 07 बजे:00 **उसका बेटा** अस्पी उर्फ हैप्पी अपनी मां हरजिंदर कौर और शिकायतकर्ता के भतीजे गुरप्रीत सिंह के साथ पंजीकरण **नम्बर** वाली मोटरसाइकिल पर हरजिंदर कौर के लिए दवा लेने गए **थे** और जब वे सांभी मोड़ पर पहुंचे तो कुलविंदर सिंह, गुरकीरत उर्फ गोरा (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने दो अन्य व्यक्तियों करनैल सिंह और बलकार सिंह के साथ उन्हें रोक दिया और उसके बाद, बलकार सिंह, जिसके हाथ में बिंदा था, ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती पर उसी का प्रहार किया।फिर, कुलविंदर सिंह ने

शिकायतकर्ता के बेटे की पीठ पर बिंदा का एक और प्रहार किया, करनैल सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती पर बिंदा प्रहार किया और याचिकाकर्ता-गुरकिरत उर्फ गोरा ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती और पीठ पर लोहे का पाइप प्रहार किया।इसके बाद, सभी हमलावर मौके से भाग गए और घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी कानूनी रूप से चिकित्सकीय जांच की गई और बाद में, 14-03-2020 को उसकी मृत्यु हो गई।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि 2000 के अधिनियम की खंड 12 के प्रावधानों के अनुसार, विधायिका का इरादा किशोर को अपराध की प्रकृति या गंभीरता के बावजूद जमानत देना है, जो कथित रूप से उसके द्वारा किया गया है और इसे केवल उन मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है जहां यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि किशोर की रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के संघ में लाने या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

जांच अधिकारी के शपथ पत्र के माध्यम से जवाब रिकॉर्ड में है और जवाब के अनुसार, यह कहा गया है कि सत्यापन पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके पिता ने

पीड़ित को चोटें पहुंचाई जबकि प्राथमिकी में नामित दो व्यक्तियों करनैल सिंह और बलकार सिंह को निर्दोष पाया गया।

राज्य के वकील ने मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में राय दर्ज की है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“इस मामले में मृत्यु के कारण के बारे में राय पहले ही 20.10.2020 पर दी जा चुकी है कि "इस मामले में मृत्यु का कारण चोटें और इसकी जटिलताएं हैं"।हमारी राय में, यह बहु-आघात का मामला था जिसमें गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम और ग्लासगो कोमा स्केल E1M1V1 के साथ सदमा था जैसा कि अस्पताल के रिकॉर्ड में बताया गया है

और शव परीक्षण और मृतक के विसरा की हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के दौरान देखे गए निष्कर्षों की पुष्टि अस्पताल के रिकॉर्ड से हुई है।हमारी राय में, चोटों के कारण होने वाली जटिलताओं में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और उसके बाद **दिल की धड़कन रूकना** शामिल थे।"

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता **कुलविन्द्र सिंह के** परिवार और याचिकाकर्ता के पिता के बीच कुलविंदर सिंह की बेटी यानी वर्तमान याचिकाकर्ता गुरकिरत @गोरा **की बहन** को घटना से लगभग 1 साल पहले मृतक अस्पी @हैप्पी द्वारा **सताने** के कारण दुश्मनी है और पंचायत में मामले से समझौता किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष से अधिक है, इसलिए उसे "वयस्क" माना जाना चाहिए और इसलिए, उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जाती है, विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 31.05.2020 के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.07.2020 आदेश को **रद्द** किया जाता है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/**इलाका** मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/मुचलका बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।"

(10) उपर्युक्त मामले के अवलोकन से पता चलता है कि जहां याचिकाकर्ता (गुरकिरत @गोरा) के खिलाफ आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती और पीठ पर लोहे की नली से प्रहार किया था, वहां भी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(11) इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने विष्णु के मामले (उपरोक्त) में भी जमानत दे दी, जहां आरोप था कि **इसमें याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई**

(विकास बहल, जे.)

थी और उसमें याचिकाकर्ता से एक खून से सना लकड़ी का डंडा बरामद किया गया था।

उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- "याचिकाकर्ता, जो कानून के साथ टकराव में एक बच्चा है, ने अपने पिता द्वारा से तत्काल याचिका दायर की है, जिसमें दिनांकित 15.01.2021, संलग्नक पी-2 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "अधिनियम") की खंड 12 के तहत जमानत देने के लिए आवेदन को प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रोहतक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा दिनांकित 02.02.2021 आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

तथ्य, संक्षेप में, यह है कि राजेंद्र की एक शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 201,302,34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (vi) (संक्षेप में "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम") के तहत इस आरोप पर प्राथमिकी 214 दिनांक 28-05-20 को दर्ज की गई थी कि अमित उपनाम नीटू और वर्तमान याचिकाकर्ता ने उनके बेटे सोमबीर की हत्या की है। जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त को 28.05.2020 पर गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने प्रकटीकरण बयान में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील, जिन्हें शिकायतकर्ता के वकील द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, एस. आई. भगत सिंह के निर्देश पर प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई और खून से सना लकड़ी की छड़ी के साथ-साथ अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी याचिकाकर्ता से बरामद की गई है।उनके निर्देशों के अनुसार, चालान 23.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है, 10.03.2021 पर आरोप तय किया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 03.06.2021 के लिए मुकदमा तय किया गया है, हालांकि अभी तक कोई भी गवाह गवाह बॉक्स में पेश नहीं हुआ है।वह प्रस्तुत करता है कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना है।प्रतिवादी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की उम्र को फिर से निर्धारित करने के लिए एक आवेदन निचली अदालत के समक्ष लंबित है।

कानून के **विरोध** में एक बच्चे को जमानत देना एक नियम है और इसे अस्वीकार करना एक अपवाद है। अधिनियम की **धारा** 12 में यह प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता या उस समय के लिए किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

अधिनियम की **धारा** 12 (1) के **प्रावधान** में निर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं को छोड़कर, कानून **का उल्लंघन करने वाले** एक बच्चे को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।अदालतें इस हद तक मान चुकी हैं कि न तो अपराध की गंभीरता और न ही यह तथ्य कि सह-अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जाना बाकी है, प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार है। **नीचे दी गई** अदालतें कानून की कानूनी स्थिति की सराहना करने में विफल रही हैं, जिसका इस अदालत ने सी. आर. आर.-862-2020 में **पालन** किया है, जिसका शीर्षक विशाल बनाम हरियाणा राज्य **है जिसका फैसला** ने 27.05.2020 **को हुआ** और सी. आर. आर.-962-2020 शीर्षक संजीव बनाम हरियाणा राज्य ने 02.07.2020 **को** फैसला किया ।

दलीलों के दौरान, प्रतिवादी न तो किसी सामग्री को दिखा सकते थे और न ही यह समझाने के लिए किसी सामग्री का उल्लेख कर सकते थे कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो क्या वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आएगा या ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आएगा।अभिलेख पर किसी भी सामग्री के बिना अभियोजन पक्ष की केवल आशंका जमानत देने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि कोई किशोर दोषी पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो अधिनियम की खंड 18 (1) (**फ**) के तहत उसे विशेष गृह में बिताने का आदेश दिया जा **सकने वाली अधिकतम अवधि 3 वर्ष है**। याचिकाकर्ता ने एक साल से अधिक समय तक कारावास में बिताया है, इसलिए याचिकाकर्ता को आगे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रोहतक द्वारा पारित **आदेश** दिनांक 15.01.2021 के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित दिनांक 02.02.2021 के आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

इस स्तर पर मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखे बिना, याचिकाकर्ता को निचली अदालत/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।"

(12) सी. आर. आर.-962-2020 में "संजीत बनाम हरियाणा राज्य" शीर्षक वाले मामले में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने 02.07.2020 पर निर्णय लेते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"यहाँ पुनः प्रस्तुत किए गए प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि **किशोर की जमानत को अस्वीकार करने के** रुकसद बनाम हरियाणा राज्य के लिए एक अपवाद बनाया गया है।

(विकास बहल, जे.)

447

जो कानून के **विरोध** में है अर्थात उसके किसी ज्ञात अपराधी के साथ आने की संभावना है या जमानत पर रिहा होने पर ऐसे किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक **खतरा होगा या किशोर की रिहाई न्याय** के उद्देश्यों को विफल कर देगी।इस तरह के अपवाद को लागू करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कुछ सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में किशोर की रिहाई अधिनियम की **धारा** 12 के तहत मान्यता प्राप्त अपवाद के अंतर्गत आएगी।

अपीलीय न्यायालय द्वारा संलग्नक पी-1 में पारित दिनांक 13-05-2020 का विवादित आदेश इस तरह के किसी भी तर्क से पूरी तरह से रहित है।आदेश में ऐसी कोई सामग्री/साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्राथमिकी **रिपोर्ट** में उल्लिखित अपराध की गंभीरता

अधिनियम की **धारा**12 के आलोक में किशोर को जमानत की रियायत से इनकार करने का आधार नहीं होगी।

(13) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिनियम की **धारा** 12 के तहत एक आवेदन में, जमानत नियम है और केवल उस स्थिति में जब अपीलकर्ता अधिनियम की खंड 12 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के तहत आता है कि जमानत आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

(14) आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम की खंड 12 के उक्त प्रावधानों पर विचार भी नहीं किया गया था और इसमें यह दूर से भी नहीं देखा गया था कि अपीलकर्ता का मामला किसी भी अपवाद के दायरे में आता है।कथित घटना के दिन अपीलकर्ता की आयु 16 वर्ष और 2 महीने थी।अभियोजन पक्ष के संस्करण के अवलोकन से पता चलता है कि 11 आरोपी हैं और हालांकि, कुछ अभियुक्तों को विशिष्ट चोट लगी थी, लेकिन वर्तमान अपीलकर्ता को कोई विशिष्ट चोट या विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता 24.07.2019 के बाद से हिरासत में है और 30 गवाह हैं, जिनमें से 15 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है और इस प्रकार, वर्तमान महामारी को देखते हुए मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है।यहां तक कि सह-अभियुक्त आमिर, जो कथित घटना की तारीख को एक वयस्क था, को पहले ही इस अदालत की एक समन्वय पीठ द्वारा सीआरएम-एम-35750-2020 में पारित 16.11.2021 के आदेश के अनुसार नियमित जमानत दे दी गई है, और उसकी हिरासत की अवधि वर्तमान अपीलकर्ता की हिरासत से कम थी।

(15) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है ।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह द्वारा पारित **दिनांक 29-04-2020 को विवादित आदेश** को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को संबंधित **विचारक** न्यायालय/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/**इलाका** मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/जमानती बांड प्रस्तुत करने के अधीन और किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं होने के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

(16) हालाँकि, ऊपर बताई गई किसी भी बात को मामले के गुण-दोष पर राय की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और निचली अदालत वर्तमान मामले में की गई टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी जो केवल वर्तमान जमानत याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं।

इंदरपाल सिंह दोआबिया

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : गीता